शोध मंथन Vol. XI No.II Apr.-June. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 7.760 (SJIF)

भारतीय गाँव मेंनिरन्तरता एवं परिवर्तन : लखनऊ जनपद के दो गाँवों एक अध्ययन

सहर हुसैन
ऐसोसिऐट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
करामत हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ।
शोधार्थिनी, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
Email: saherhussain36678@gmail.com

सारांश

भारत गाँवों की भूमि है, जहाँ देश की दो तिहाई जनसंख्या निवास करती है। भारत क्रांतिकारी बदलावों के दौर से गुजर रहा है, जिससे गाँव भी अछूते नहीं रहे हैं। ग्रामीण समाज का परिवर्तन जीवन के हर हिस्से में देखा जा सकता है। इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों कारक उत्तरदायी हैं। आज गाँवों की कृषि आधारित आजीविका भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा का प्रसारण, मीडिया का आगमन, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और प्रवासन आदि से प्रभावित हुई है। इसलिए ग्रामीण भारत में जीवन शैली, दृष्टिकोण और विचारों में परिवर्तन आया है। आज पारम्परिक ग्रामीण समाज एक गतिशील समाज में बदल गया है।

मुख्य शब्दः *आय, गतिशीलता, ग्रामीण शिक्षा, परिवार, मोबाइल।*

प्रस्तावना

भारतीय ग्रामीण समाज की आधिकांश जनता की मुख्य आजीविका कृषि अथवा कृषि आधारित पर होने के साथ–साथ सीजनल माइग्रेशन पर आधारित हो गयी है। नगरों में जाकर यह ग्रामीण प्रवासी अपनी आय के साथ–साथ आधुनिक विचारों में वृद्धि करते हैं। जीवन के विभिन्न पक्षों में आधुनिक तकनीकी, तर्कसंगत विचारों के प्रचार–प्रसार एवं अनुपालन से शहरों के साथ ग्रामीण समाज में भी शिक्षा, नवीन उद्यमों, जीवन प्रत्याशा, जन–स्वास्थ्य एवं लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि हुई है। वर्तमान अध्ययन ग्रामीण जीवन का गठन करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण घटकों को समझने का एक प्रयास है।इसमें लोगों के व्यवहार परीक्षण और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मूलभूत तथ्यों का विभिन्न सामाजिक समूहों, सामाजिक संरचना, जाति, परिवार, नातेदारी आदि का अध्ययन किया गया है। अर्थव्यवस्था, निर्णय लेने के विकल्प तथा राजनीति का विभिन्न क्षेंत्रों में सामाजिक अंतःक्रियाओं या परस्पर क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले तत्वों का विश्लेषण भी किया गया है। यह अध्ययन ग्रामीण समाज का नगरीय क्षेत्रों के बीच अन्योन्याश्रय दिखाता है, जिसमें ग्रामीण समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक

पक्षों का समग्र प्रस्तुतीकरण है।

नवाबों के शहर के रूप में मशहूर लखनऊ अपने आप में अनेकों सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहरों को समटे हुए है। यहां की मिट्टी की खुशबू फलों के राजा आम के माध्यम से देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुँचती रहती है। लखनऊ हमेशा ही अपनी गंगा–जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक संस्कृतियों का सम्मिलन है। मुगल शासकों के साथ अंग्रेजी हुकूमत के लिए भी यह शहर हमेशा ही पसंद किया जाता रहा है। यही कारण है कि यहाँ सामाजिक समरसता एवं भाईचारे के साथ सामाजिक परिवर्तन एवं निरंतरता के अंश साथ–साथ चलते हैं।

ग्रामीण समाज में निरंतरता और परिवर्तन पर आधारित यह अध्ययन लखनऊ जनपद की मलिहाबाद तहसील में स्थित जिंदौर ग्राम पंचायत के दो राजस्व ग्रामों बाकीनगर और रहीमाबाद में विकास और सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करता है। यह दोनों गाँव लखनऊ–हरदोई राज्य मार्ग पर लखनऊ जिला मुख्यालय से लगभग 45 किमी दूर स्थित हैं। यह शोध कार्य रहीमाबाद और बाकीनगर गाँवों का अध्ययन एक मायने में अद्वितीय है, क्योंकि इन दोनों ग्रामों या ग्राम पंचायत जिंदौर में से कोई भी गाँव कभी भी इस प्रकार के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में शामिल नहीं रहा है, जिसमें सैद्धान्तिक रूप से निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन किया गया हो। दोनों ग्रामीण समुदायों की समाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि समान है, इसलिए यह ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया गया है कि अध्ययन तथ्यों में विषमता की सम्भावना कम हो सके।

उद्देश्य

वर्तनमान अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक संरचना में परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कारकों का अध्ययन करना है, जो गाँवों के जीवन में आर्थिक विकास व जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा, संचार और अन्य परस्पर सम्बंधित पहलुओं की प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। इस अध्ययन के निम्न उप–उददेश्य है।

1. ग्रामीण की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को समझना।
2. गाँव में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. गाँव के सांस्कृतिक व राजनीतिक परिवर्तनों को समझना।
4. गाँव में लिंगभेद का विश्लेषण करना।

अध्ययन पद्धति

इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प का उपयोग किया गया है। अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से एकत्र किये गये तथ्यों पर आधारित है। प्राथमिक दत्त संकलन के लिए मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों विधियों को अपनाया गया है। मात्रात्मक तथ्य जनसंख्या, शिक्षा, निर्णय के विकल्प आदि पर एकत्र किये गये थे जबकि गुणात्मक तथ्य मानव व्यवहार, आदतों, पहनावा, स्वास्थ्य राजनीतिक हित आदि पर एकत्र किये गये थे। गहन साक्षात्कार, केन्द्रित समूह चर्चा हेतु अनौपचारिक बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें समाज

वैज्ञानिक नियमों यथा–गोपनीयता आदि का पालन किया गया। दत्त संग्रह के विभिन्न तरीकों के माध्यम में ग्रामीण जीवन में सामाजिक –आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व संचार के प्रभाव की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया गया।

इसमें गाँवों का समग्र अध्ययन करने का प्रयास किया है। ग्रामीणों के बीच मात्रात्मक जानकारी एकत्र करने हेतु तीन सौ साक्षात्कार अनुसूचियों को भरा गया गया। साक्षात्कार अनुसूची में पाँच पहलुओं, (1) व्यक्तिगत जानकारी (प्रोफाइल) (2) सामाजिक संगठन (3) आर्थिक संगठन (4) राजनीतिक संगठन आदि शामिल किये गये थे।

साहित्य समीक्षा

ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञानी **फ्रेड्रिक जॉर्ज बेली** (1958/1964) ने भारत के एक गाँव बिशिपारा (ओडिषा) में बाहरी ताकतों के प्रभाव से सामाजिक संरचना में हुए बदलावों का विश्लेषण किया था। यह अध्ययन ऐसी दो निम्न जातियों पर आधारित था जो, उस क्षेत्र में योद्धा जातियों के रूप में प्रचलित हैं। भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न प्रभुता, ब्रिटिश शासन की कार्यप्रणाली उनकी पारम्परिक खण्डात्मक जातीय संरचना में बदलाव के लिए सुगमता प्रदान कर रही थीं। इस अवसर का लाभ उठाकर इन जातियों ने संस्कृतीकरण कर अपनी जातियों को प्रभु जातियों के रूप में पहचान बनाने का प्रयास किया।

विश्व प्रसिद्ध सामाजिक मानवशास्त्री **मैकिम मेरिअट (1955)** ने अपनी पुस्तक **विलेज इण्डिया** में अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के ग्रामों का अध्ययन प्रस्तुत किया था। यह अध्ययन भारत के ग्रामों का अन्य समुदायों एवं सभ्यताओं के साथ अन्तःसम्बन्ध को दर्शाता है, फिर भी इस ग्रामीण अध्ययन को भारत के लाखों ग्रामों का प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन का दावा करना मूर्खतापूर्ण होगा (Marriott, Mckim, 1955: vii)।

रॉबर्ट वाडे (1988/1994) दक्षिण भारत के ग्रामों में किये गये क्षेत्रीय अध्ययन से यह उत्तर पाते हैं कि गाँव की सामाजिक संरचना, जनांकिकीय सम्मिश्रण, गाँव का बाहर के बाजार से सम्बन्ध, एवं सामूहिक कार्य की उद्घोषणा में राज्य के तंत्र की अहम् भूमिका के साथ अनुपलब्धता एवं जोखिम आदि कारण हैं। उनका यह अध्ययन छोटी राजनीति एवं औपचारिक राजनीति की उत्पत्ति का एक ''सार्वजनिक क्षेत्र (क्षमता)'' के उद्भव का अध्ययन है।

एडवर्ड सिम्पसन (2016) ने ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के ऐसे गाँवों का पुनः अध्ययन किया जो 1950 के दशक में ब्रिटिश मानवविज्ञानी एफ.जी. बेली (विशीबारा), एड्रियन सी मेयर (जमगोड) और डेविड एफ. पोकॉक (सुन्दराना) द्वारा अध्ययन किये जा चुके थे। इस अध्ययन के माध्यम से 1950 के सामाजिक जीवन की स्थितियों के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें ब्रिटिश उपनिवेश से आजाद भारतीय गाँवों में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों का परीक्षण किया गया है। उपनिवेशवादी प्रशासन द्वारा भारतीय ग्रामों का एक (ग्राम गणराज्य) के रूप में मनमोहक चित्रण किया था, जिसने अमेरिका एवं ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञानियों को यहाँ के गाँवों का क्षेत्रीय अध्ययन करने हेतु आकर्षित किया (Simpson, 2016; Simpson and Jeffery et al2018)।

टोमासो सब्रिकोली (2016) ने मध्य प्रदेश में स्थित देवास जनपद के जमगोड़ गाँव, जिसका अध्ययन 1950 के दशक में ए.सी. मेयर ने किया था का सन् 2012–14 में दोबोरा अध्ययन किया। उन्होंने ''**भूमि, श्रम और शक्ति**'' पर लेख के माध्यम से गाँवों में भूस्वामित्व एवं उसके उपयोग में बदलाव तथा उत्पादन एवं श्रम के सम्बन्धों का अवलोकन प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन स्थानीय शक्ति संरचना एवं व्यक्तिगत आकांक्षाओं में हो रहे बदलावों को दर्शाता है।

लन्दन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइंस के शोधकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पालनपुर गाँव जो 1950 के दशक से ही समाज वैज्ञानिकों द्वारा गरीबी एवं परिवर्तन के अध्ययन के लिए केन्द्र रहा है, में पिछले सात दशकों में हुए बदलावों का विकास के विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन किया। अध्ययन दल ने जमींदारी उन्मूलन, हरित क्रान्ति, शिक्षा, सामाजिक एवं जनांकिकीय संरचना में बदलाव, संचार में परिवर्तन आदि पर तथ्य एकत्र किये थे। यह अध्ययन 1957/8 से लगातार भारत के विकास को एक गाँव के अनुभव से समझने का प्रयास है, जिसमें 100 प्रतिशत घरों को सर्वेक्षण किया जाता रहा है। इस गाँव में सबसे गरीब जाति– जाटव की उन्नति को भी देखा गया है (Himanshu and Stern,2011)।

अनिल कुमार (2019) ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में गगां तटीय ग्रामों में निरन्तरता एवं गत्यात्मकता पर अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परम्पराओं, संस्कारों एवं कर्मकाण्डों का हमारे स्वास्थ्य एवं सामाजिक पारिस्थितिकी पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अपने एक अन्य अध्ययन, जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सुविधाहीन किसानों की आजीविका पर किया था। इसमें यह बताने का प्रयास किया कि ग्रामीण जीवन हेतु उनकी कृषि आधारित आजीविका को मजबूत एवं पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है (Kumar, 2018b), किन्तु वर्तमान कषषिगत एवं सामाजिक–राजनीतिक दशाओं में यह सम्भव नहीं है।

शोध परिणाम

सम्पत्ति बंटवारे का आधार

परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है, जिसमें पूजा एवं संपत्ति पर सभी सदस्यों में सामूहिक अधिकार होता है। उत्तर भारत में सभी समुदायों में पित्रसत्तात्मक परिवार पाये जाते हैं। परिवार में संपत्ति के बंटवारे में भी पित्रसत्तात्मकता की झलक दिखाई पड़ती है। भारत में महिलाओं को पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार पर समान अधिकार हो चुका है, किन्तु विभिन्न धर्म आज भी विरासत के पारम्परिक कानूनों का पालन करते हैं। तालिका संख्या–1 के अनुसार 78.67 प्रतिशत परिवारों में पैतृक सम्पत्ति का अधिकांश भाग बेटे को विरासत में मिलता है। अध्ययन क्षेत्र के 18.66 प्रतिशत परिवारों में दोनों (बेटी तथा बेटे) को सम्पत्ति में हिस्सा दिया जाता है। मात्र 2.67 प्रतिशत परिवारों में केवल बेटी को इसलिए हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि उनके माता–पिता अपने बेटों से खुश नहीं थे अथवा उनके परिवार में कोई बेटा नहीं था।

तालिका–1:सम्पत्ति बंटवारे में लैंगिक आधार

मुखिया से सम्बन्ध	संख्या	प्रतिषत
पुत्र	236	78.67
पुत्री	8	2.67
दोनों	56	18.66
योग	**300**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से भारतीय समाज की पित्रसत्ता की मजबूती भी दिखाई देती है, लेकिन साथ ही विभिन्न नियमों एवं परियोजनााओं के प्रभावस्वरूप सामाजिक गतिशीलता भी प्रकट होने लगी है। अनलि कुमार के अनुसार भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए जो बाधाएं हैं वह घर, समुदाय, बाजार और राज्य के स्तर पर लैंगिक विषमता के अभ्यास की l ad fr] l kekft d l apukvkaS i z uu i fØ; kdhxgj kbZ esafufgr gS(Kumar, 2018b)।

परिवार में निर्णायक भूमिका

भारत में अधिकांश सरकारों ने कई कानूनों और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से लिंगभेद को कम करने की कोशिश की है। हमारे समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है। जीवन–साथी चुनना एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो सामान्यतः एक व्यक्ति के माता–पिता, परिवार, रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। विवाह पति एवं पत्नी के बीच सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त संघ है, जो उनके तथा उनसे जन्में बच्चों के अधिकारों और दायित्व की स्थापना करता है। विवाह दो परिवारों का मिलन है, जिसमें भावनात्मक रूप से स्थिर और परिपक्व माता–पिता अपने बच्चों को साझा मूल्यों के साथ लालन–पालन करते हैं। आज भी विवाह हेतु परिवार द्वारा निर्णय को सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें परिवर्तन को देखा जा सकता है, क्योंकि आजकल लड़की या लड़के की राय को भी ध्यान में रखा जाता है। जीवन–साथी चयन हेतु 71.33 प्रतिशत मामलों में परिवार, 25.34 सगे सम्बन्धियों/नातेदार द्वारा तथा केवल 3.33 प्रतिशत मामलों में लड़के या लड़की द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाता है (तालिका–2(क)।

तालिका–2: जीवन–साथी चयन तथा आगे की शिक्षा में निर्णायक भूमिका

विवरण	संख्या	प्रतिशत
क. जीवन–साथी चयन में निर्णायक भूमिका		
परिवार	214	71.33
नातेदार/सम्बन्धी	76	25.34
स्वयं	10	3.33
ख. आगे की शिक्षा में निर्णायक भूमिका		
परिवार के वरिष्ठ सदस्य	82	27.33
पिता	78	26.00
माता–पिता	44	14.67
स्वयं	96	32.00
योग	**300**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण।

शिक्षा समाज में समरसता, समानता एवं लाकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने का मार्ग है। तालिका–2(ख) के अनुसार 27.33 प्रतिशत मामलों में शिक्षा का निर्णय परिवार के बुजुर्ग/वरिष्ठ सदस्य सदस्यों के परामर्श से लिया जाता है, जिसमें जीवन का अनुभव होता है। संयुक्त परिवारों में कभी–कभी ताऊ, दादा भी उच्च अध्ययन के लिए अंतिम निर्णय का हिस्सा होते थे। शिक्षा सम्बन्धी 26 फीसदी मामलों में पिता ही अंतिम निर्णय लेता है, जबकि14.67 प्रतिशत मामलों में माताओं से भी सलाह ली जाती है।युवा दिमाग हालिया रूझानों और समाज की मांगों के बारे में जानते हैं। वह विभिन्न सूचनाओं के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं और अपडेट रहते है। आज समाज में गतिशीलता एवं जागरूकता के परिणामस्वरूप लगभग एक–तिहाई परिवारों में विद्यार्थी स्वयं निर्णय लेते हैं।

पारिवारिक विवाद निपटारा

आरम्भ से ही समाज में संघर्ष एवं सहयोग दोनों ही प्रक्रियाएं चलती रही हैं। अध्ययन क्षेत्र में पारिवारिक विवादों का निपटारा 60 प्रतिशत परिवारों द्वारा स्वयं ही कर लिया जाताहै, जबकि 32 प्रतिशत मामलों में सगे सम्बन्धी द्वारा, 8 प्रतिशत पुलिस एवं न्यायालय द्वारा किया जाता है। आजकल कोई भी पारिवारिक विवादका निपटारा पंचायत द्वारा नहीं किया जाता है (**तालिका–3**)। वैवाहिक संघर्ष में ससुराल के रिश्तेदार या कुछ रिश्तेदार जो समाज में उच्च स्थान रखते हों, उनसे परामर्श किया जाता है तथा उनके निर्णय को सम्मान किया जाता है और उसे अंतिम माना जाता है।

तालिका–3: पारिवारिक विवाद निपटारा निर्णायक भूमिका

निर्णय लेने वाला सदस्य	संख्या	प्रतिशत
परिवार	180	60.00
नातेदार/सम्बन्धी	96	32.00
पुलिस एवं कोर्ट	24	8.00
योग	**300**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण।

संचार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

आज गाँवों में यह सम्भव है कि लोगों के पास अन्य बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी न होती हो, लेकिन वह मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। आज सभी जगह मोबाइल कनेक्टीविटी है; परिणामस्वरूप 34.00 प्रतिशत परिवारों के पास एक मोबाइल फोन, 51.33 प्रतिशत परिवारों के पास दो मोबाइल फोन तथा 14.67 प्रतिशत परिवारों के पास दो से अधिक मोबाइल है (तालिका–4(क)। जहाँ कोई नहीं है मोबाइल कनेक्टीविटी ने दुनिया से सीधा सम्पर्क बढ़ाया है। एक से अधिक मोबाइल फोन रखने वाले परिवार अपनी बढ़ती हुई सामर्थ्य और गोपनीयता की भावना को दर्शाते है।

तालिका–4(ख) में दिखाया गया है कि 71.34 प्रतिशत परिवारों के पास स्मार्ट फोन

उपलब्ध है, जबकि 28.66 प्रतिशत के पास की–पैड फोन हैं। आमतौर पर युवा अपनी पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। ग्रामीणों में गतिषीलता बढ़ी है, जो महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं उन्हें स्मार्टफोन रखना बहुत पसंद है। उनका मानना है कि इसने काम को आसान बनाने के साथ रिश्तेदारों से जोड़े रखने में मदद की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपने मिशन अंत्योदय के हिस्से के रूप में किए गए एक हालिया सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से अधिक मोबाइल कनेक्टीविटी वाले गाँव है।

तालिका–4: परिवार में उपलब्ध मोबाइल फोन– संख्या, स्वरूप व उपयोग

विवरण	संख्या	प्रतिशत
क. मोबाइल फोन की संख्या		
एक	102	34.00
दो	154	51.33
दो से अधिक	44	14.67
ख. स्मार्ट फोन का पैषन		
स्मार्ट फोन	214	71.34
की पैड	86	28.66
ग. मोबाइल फोन उपयोग का उद्देश्य		
केवल वार्तालाप	78	26.00
वार्तालाप एवं संदेश भेजना	44	14.67
वार्तालाप, संदेष एवं अन्य उपयोग	178	59.33
योग (N)	**300**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण।

मोबाइल फोन की उपयोगिता में विविधता आयी है। तालिका–4(ग) के अनुसार 26 प्रतिशत परिवार मोबाइल फोन का उपयोग वार्तालाप हेतु; जबकि 14.67 प्रतिशत परिवार वार्तालाप और संदेश दोनों के लिए करते हैं। अधिकांश परिवार (59.33 प्रतिशत) बहुसंख्यक वार्तालाप, संदेश और अन्य एप्लिकेशन संदेश और अन्य एप्लिकेशन श्रेणी (जिसमें शिक्षा सामाजिक नेटवर्किंग गेम, वीडियो, संगीत आदि शामिल है) के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। जहाँ एक ओर वृद्ध और अशिक्षित लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल वार्तालॉप के उद्देश्य से करते हैं; तो दूसरी ओर छोटे बच्चे व महिलाएँ अपने खाली समय में गेम खेलते है, गाने सुनते है और वीडियो देखते हैं। गाँव में एक व्यक्ति जिसके पास कोई टेलीविजन नहीं है अपने हैंडसेट पर वीडियो और फिल्में देख सकता है।

परिवार में शिक्षा का प्राविधान एवं माध्यम

भारत के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा न केवल गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए

महत्वपूर्ण है, अपितु विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में भी महत्वपूर्ण है। सर्वशिक्षा अभियान सहित कई सरकारी योजनाओं के कारण शायद ही ऐसे परिवार हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे है। स्कूल जाने वाले इन दोनों गाँवों के 98.33 प्रतिशत परिवार हैं, जिनमें से बालिकाएं भी निजी या सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जबकि 1. 67 प्रतिशत परिवारों की बालिकाएं अपनी व्यक्तिगत समस्याओं यथा– स्वास्थ्य, विकलांगता जैसे कारणों से स्कूल नहीं जा पाती हैं अथवा उनके पास कोई अभिभावक नहीं है (**तालिका–5**)।

वर्तमान समय में यह एक चिंता का विषय है, कि युवाओं की शैक्षिक पसंद उनकी विभिन्न आकांक्षाओं के साथ कैसे तालमेल बैठाती है। तालिका–5 में दिखाया गया है 62.66 प्रतिशत युवा रोजगारपरक शिक्षा जैसे–बी0टेक0, बी0एड0 (आमतौर पर लड़कियाँ), सिलाई, ब्यूटीशियन, आशुलिपि, टाइपिंग, कम्प्यूटर, पाठ्यक्रम आदिकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। आमतौर पर लोग अपनी बेटियों को पेशेवर शिक्षा के लिए गाँव से बाहर भेजने से बचते रहे हैं; किन्तु कुछ ग्रामीणों का अभी भी मानना है कि इससे लड़कियों की आर्थिक निर्भरता में कमी आ सकती है। कुछ परिवारों ने सुरक्षा कारणों से अपने बच्चों को शहर नहीं भेजा।

तालिका–5: परिवार में षिक्षा ग्रहण सम्बन्धी विवरण

विवरण	**संख्या**	**प्रतिशत**
परिवार में शिक्षा का प्राविधान		
बालिका शिक्षा का प्राविधान	295	98.33
रोजगार परक शिक्षा का प्राविधान	188	62.66
शिक्षा का माध्यम		
अंग्रेजी माध्यम	83	27.66
हिन्दी माध्यम	217	72.34
योग (N)	**300**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण।

भारतीय गाँव में शिक्षा का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण युवा पुरूष और महिलाएँ अपने माता–पिता के शिक्षा के स्तर को पार कर रहे हैं। जैसा कि तालिका–5 में दिखाया गया है 27.66 प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चों ने पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी चुना है, जबकि 72.33 प्रतिशत बच्चों ने हिंदी माध्यम संस्थानों (ज्यादातर सरकार) में पढ़ रहे हैं। जो माता–पिता निजी शिक्षा और परिवहन खर्च वहन कर सकते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को संडीला, मलिहाबाद और कुछ लखनऊ में पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्थानीय स्तर पर भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की उपलब्धता है।

महिलाओं द्वारा आर्थिक अर्जन में सहयोग

आजकल महिलाएं समाज में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तालिका–6 में दिखाया गया है कि 77.34 प्रतिशत परिवारों में महिलाओं द्वारा पारिवारिक आय

में योगदान किया जाता है; जबकि केवल 22.66 प्रतिशत का परिवारों में महिलाएं आय में कोई योगदान नहीं देती हैं। क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान पाया गया कि आमतौर पर गरीब परिवारों की महिलाओं ने स्वयं के क्षेत्र अथवा बाहर से कमाकर पारिवारिक आय में योगदान दिया है। खासतौर पर जब परिवार में विवाह अथवा पुरूष सदस्य के स्वास्थ्य का मुद्दा होता है, तो महिलाएँ भी कमाने निकलती हैं। आजकल ग्रामीण महिलाएं प्राथमिक स्कूल शिक्षा, सरकारी अस्पताल, निजी क्लीनिकों में सहायक/नर्स का काम करती हैं। निजी दुकानों पर पुरूषों की अनुपस्थिति में दुकानों का संचालन करती हैं। निम्न जाति की महिलाओं ने पारम्परिक और अकुशल काम किया जबकि उच्च जाति की महिलाओं ने ज्यादातर महिलाएँ अध्यापन, चिकनकारी, जरदोजी, पार्लर, कम्प्यूटर सेंटर में काम किया।

तालिका–6: परिवार में महिलाओं द्वारा आर्थिक अर्जन में सहयोग

महिलाओं द्वारा आर्थिक अर्जन में सहयोग	संख्या	प्रतिशत
सहयोग किया जाता है	232	77.34
सहयोग **नहीं** किया जाता है	68	22.66
योग	**300**	**100**

स्रोतः शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण।

निष्कर्ष

लखनऊ के ग्रामीण समाज में नगरीय जीवन से जड़ी अनेक सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण युवा, महिलाएं शिक्षा, रोजगार आदि के लिए नगरीय क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो रही हैं। शिक्षा की ओर बढ़ते झुकाव ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। महिलाओं द्वारा पारिवारिक जीवन में निर्णय लेने, आर्थिक अर्जन कर जीवन के विभिन्न पक्षों में तर्कसंगत विचारों के पनपने हेतु बल प्रदान किया है। संचार में आधुनिक तकनीकीका प्रयोग भी ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन का कारक सिद्ध हो रहा है। गाँव के किसी भी परिवार के निर्णय, विवाद का निपटारा पंचायत के माध्यम से नही किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 Bailey, FG (1958/1964) *Caste and Economic Frontier: A Highland Orissa Village*, Bombay: Oxford University Press (Indian Branch).

2 Himanshu and Stern, Nicholas (2011) India and an Indian village: 50 years of economic development in Palanpur, Report to Department for International Development, *London School of Economics and Political Science*. https://sticerd.lse.ac.uk/india/research/palanpur/default.asp.

3 Kumar, Anil (2018a) *Gender Dimensions in Small Tea Gardens: An Analysis of Labour Relations in Two Districts of North Bengal*, in PK Singh and Amit Bhowmik (Ed.) Women on the Edge of Progress: Reflections from Third World Countries, New Delhi, Adhyayan Publishers & Distributors, pp-**99-108**.

4 Kumar, Anil (2018b) Challenges in Adopting Modern Farming Practices by Resource Poor Farmers: A Case of Eastern Uttar Pradesh, *The Eastern Anthropologist*, Vol. 71, No.1-2, pp-**15-39.**

5 Marriot, Mckim (1955) *Village India: Studies in the Little Community*, Chicago, The University of Chicago Press.

6 Sbriccoli, Tommaso (2016) Land, Labour and Power, *Economic and Political Weekly*,Vol. 51, Issue No. 26-27.

7 Simpson, Edward (2016) Village Restudies: Trials and Tribulations, *Economic and Political Weekly*, Vol. 51, Issue No. 26-27.

8 Simpson, Edward and Jeffery, Patricia et al (2018) *RURAL CHANGE AND ANTHROPOLOGICAL KNOWLEDGE IN POST-COLONIAL INDIA: A COMPARATIVE 'RESTUDY' OF F.G. BAILEY, ADRIAN C. MAYER AND DAVID POCOCK, 1950-2012*; Colchester, Essex: UK Data Archive. 10.5255/ukda-sn-852771.

9 Wade, Robert (1988/1994) Village Republics: Economic Conditions for Collective Action in South India, California, International Centre for Self-Governance.

10 कुमार अनिल (2019) हिन्दू सामाजिक संरचना एवं कर्मकाण्डीय गत्यात्मकता में राज्य व नागर समाज की भूमिका: नमामि गंगे कार्यक्रम के सन्दर्भ में एक केस अध्ययन, *शोधमंथन,* खण्ड–10, अंक: 02 ।